'Varanasi to be a part of national waterway grid'

Binay.Singh@timesgroup.com

Varanasi: The central government is going to invest Rs 22,000 crore to develop an integrated National Waterways Transportation Grid for the promotion of cheaper and environment friendly supplementary mode of transportation. The Inland Waterways Authority of India (IWAI) is working on this plan. The stretch of Ganga passing through Varanasi, the parliamentary constituency of Prime Minister Narendra Modi, will also be the part of this grid.

"We are working on the development of National Waterways Transportation Grid to provide a supplementary mode of transport in the country by joining the declared National Waterways," said IWAI chairman Amitabh Verma. He was was here on Friday to take part in a workshop on inland water transport sector. According to him, the project would cost Rs 22,000 crore.

He said the water transport is not only cheaper but also fuel-efficient and environment friendly mode of transport. So far five waterway stretches have been declared as National Waterways, while the sixth (Barak River between Lakhipur and Bhanga in Assam) is in the process for declaration as National Waterway 6. The declared five waterways include River Ganga from Haldia to Allahabad (NW-1), River Brahmaputra from Dhubri to Sadiya (NW-2), West Coast Canal from Kottapuram to Kollam with Udyogmandal and Champakara Canals (NW-3), Kakinada – Puducherry stretch of canals with River Godavari and River Krishna (NW-4), and East Coast Canal with River Brahmani and River Mahanandi's delta (NW-5).

'Need 2 barrage between Varanasi & Allahabad'

▶Continued from P 1

The states like UP and Bihar have no such directorate, he said.

"Besides, the governments would also be urged to give incentive to industries to encourage them for setting industrial units near river banks," he said further adding that unlike China, where most industries are located on the banks of rivers, no such policy decision was taken in India after Independence.

The states could undertake dredging operation in rivers to maintain required depth for navigation, he said adding that the IWAI had started cruise service between Patna and Varanasi to promote tourism in this area. Presently the cruise could be operated in this stretch only for three months, as there was no sufficient water (or depth) in the river after October. He said that efforts would be made to keep the cruise operational at least for six months. "There is need of two barrage between Varanasi and Allahabad and two barrages between Varanasi and Ghazipur to maintain navigational depth (3 meters) in this region of Ganga," he said.

Verma further said that water transportation would not affect the river adversely.

बाढ़ बाद बनारस-गाजीपुर के बीच ड्रेजिंग

❑ हल्दिया-इलाहाबाद जल परिवहन पर वाटरवेज अथॉरिटी ने बढ़ाए अपने कदम

गंगा में जल परिवहन परियोजना

- बक्सर से बनारस के बीच तीन मीटर गहराई बनाए रखने की कवायद

वाराणसी : गंगा में जल परिवहन के लिए विश्व बैंक के 4200 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ने कर दी है। इस क्रम में बाढ़ उतरते ही वाराणसी से गाजीपुर के बीच गंगा में ड्रेजिंग शुरू कर दी जाएगी। यह ड्रेजिंग क्रूज व मालवाहक पोत के गंगा में चलने योग्य जलस्तर को बनाए रखने के लिए की जाएगी। यह भी निर्णय लिया जा चुका है कि बक्सर से इलाहाबाद के बीच कम से कम तीन बैराज बनाए जाएंगे।

गंगा में जल परिवहन प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए अथॉरिटी के चेयरमैन अमिताभ वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि हल्दिया से इलाहाबाद के बीच 1620 किलोमीटर जल परिवहन का प्रोजेक्ट वर्ष 1986 में ही संसद ने पास कर दिया था। इतने वर्षों में केंद्र सरकार ने इस बाबत बजट मुहैया नहीं कराया इसलिए विलंब हुआ। अब वर्ल्ड बैंक की सहायता मिलने से बात बढ़ी है। चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि फिलहाल हल्दिया से फरक्का के बीच बिना किसी बाधा के गंगा में जल परिवहन के जरिए मालवाहक ज़हाज चल रहे हैं, नदी में तीन मीटर से अधिक गहराई मिलने की वजह से। इसके अपस्ट्रीम में बक्सर तक भी हम तीन मीटर की गहराई बनाए हुए हैं और क्रूज आदि का संचालन हो जा रहा है। दिक्कत बक्सर से ऊपर के रास्ते में है, खासकर इलाहाबाद तक। सबसे बड़ी चुनौती बक्सर से इलाहाबाद के बीच जलपोत चलाने योग्य जलस्तर बनाए रखने की है। वजह यह कि बाढ़ में तो क्रूज आदि चल भी जा रहे लेकिन पानी घटते 30 अक्टूबर के बाद क्रूज संचालन भी नहीं हो पाएगा।

टर्मिनल के लिए और जमीन देख रहे

इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के चेयरमैन ने बताया कि मालवाहक जलपोत से सामान को लोड-अनलोड करने के लिए टर्मिनल बेहद जरूरी है। बनारस में टर्मिनल के लिए 15 एकड़ जमीन ली जा चुकी है जो कम है। हम 20 एकड़ जमीन और लेने का विचार कर रहे हैं। अच्छे टर्मिनल के लिए 40 एकड़ जमीन ठीक होती है। श्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि गंगा में जल परिवहन से जुड़े प्रोजेक्ट को अगले पांच से छह साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सीपीडब्ल्यूडी के साथ ही अधिकांश कार्य आउटसोर्सिंग से कराए जाएंगे।

35 एमटी कोयले की ढुलाई अहम

चूंकि काफी मात्रा में कोयला आयात किया जा रहा है जो बंगाल की खाड़ी पहुंचता है। अब समुद्र से इलाहाबाद तक गंगा का रास्ता मिल जाने पर इस रास्ते में पड़ने वाले 21 पावर प्लांटों को कोयला सीधा पहुंचाना आसान होगा। करीब 35 मिलियन टन कोयले की ढुलाई गंगा में परिवहन शुरू होने से आसान हो जाएगी।

जल परिवहन में रोजगार की आपार संभावनाएं

होटल क्लार्क में जल परिवहन पर आयोजित कार्यशाला में बोलते अमिताभ वर्मा।

वाराणसी : इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी के चेयरमैन अमिताभ वर्मा ने कहा कि जल परिवहन के क्षेत्र में असीम अवसर उपलब्ध हैं। खासकर रोजगार की अपार संभावना है।

ऐसे में गंगा में हल्दिया से इलाहाबाद तक जल परिवहन शुरू होने से न सिर्फ उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होगा बल्कि तटवर्ती शहरों में युवाओं व दक्ष लोगों को रोजगार मिलेंगे। श्री अमिताभ शुक्रवार को छावनी क्षेत्र स्थित एक होटल में आशा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ मरीन टेक्नालॉजी के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की योजना जल मार्ग विकास को मूर्त रूप देने व पर्यटन को बढ़ावा देने की है। कार्यशाला में नॉटीकल एडवाइजर कैप्टन एसके पांडा, कैप्टन इन्द्रवीर सोलंकी, इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डा. अवधेश सिंह, दीनानाथ झुनझुनवाला, आदि लोग मौजूद थे।

टर्मिनल के लिए ली जाएगी 40 एकड़ जमीन

रामनगर में ठहरेंगे जलपोत

अमर उजाला ब्यूरो

जल परिवहन

15 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द होगी फाइनल

25 एकड़ जमीन के लिए भू-स्वामियों से की जा रही है बातचीत

वाराणसी। गंगा में जल परिवहन के लिए रामनगर में 40 एकड़ भूमि पर टर्मिनल बनेगा। इसके लिए 15 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाकी 25 एकड़ जमीन के लिए भू-स्वामियों से बातचीत चल रही है। यह जानकारी इनलैंड वाटरवेज अथारिटी ऑफ इंडिया (आईडब्ल्यूएआई) के निदेशक अमिताभ वर्मा ने शुक्रवार को क्लार्क होटल में आयोजित कार्यशाला में जानकारी दी।

कार्यशाला जहाजरानी मंत्रालय की संस्था आईडब्ल्यूएआई की ओर से इलाहाबाद-हल्दिया जलमार्ग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। 'जलपरिवहन : संभावनाओं का एक क्षेत्र' विषयक इस कार्यशाला में आईडब्ल्यूएआई के अधिकारी, मर्चेंट नेवी से जुड़े लोग, बैंक कर्मी व उद्यमी शामिल हुए। आईडब्ल्यूएआई के निदेशक अमिताभ वर्मा ने बताया कि जल परिवहन शुरू होने के बाद बनारस से सीमेंट, खाद, अनाज, कोयला, भारी मशीन, कॉलीन सहित अन्य सामानों की ढुलाई में आसानी होगी। उन्होंने उद्यमियों और व्यापारियों से आगे बढ़कर इस परियोजना में सहयोग करने और लाभान्वित होने का आग्रह किया। इस दौरान लोगों ने उनसे सवाल भी किए। जहाजों के संचालन में कछुआ सेंचुरी से आने वाली दिक्कत के सवाल पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण और विकास दोनों जरूरी है। जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। कहा कि 400 जहाज कोलकाता से इलाहाबाद के बीच चलेंगे। केंद्र सरकार के नॉटिकल एडवाइजर कैप्टन एलके पांडा, इंस्टीट्यूट के निदेशक इंद्रवीर सोलंकी, डॉ. अवधेश सिंह ने प्रेजेंटेशन के जरिये जलपरिवहन प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उपस्थित लोगों में उद्यमी आरके चौधरी, दीनानाथ झुनझुनवाला, ट्रैवेल असिस्टेंस के मालिक रोनाल्ड बेंजमिन नाडर प्रमुख थे। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. राकेश सिंह ने किया।

कार्यशाला को संबोधित करते आईडब्ल्यूएआई के निदेशक अमिताभ वर्मा *(दाएं से दूसरे)*।

उम्मीदों को लगे नए पंख

जलमार्ग से पर्यटक काशी का एक अलग अंदाज में दर्शन कर पाएंगे। इससे निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं, वाटर स्पोर्ट की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। - मृत्युंजय मिश्रा, सहायक निदेशक, पर्यटन मंत्रालय

जलपरिवहन अन्य माध्यमों से सस्ता है। इससे माल ढुलाई में कम खर्च आएगा। जाहिर है इससे वस्तुओं की कीमत में भी कमी आएगी। नए रोजगार सृजित होंगे। - आनंद दुबे, इंजीनियर मर्चेंट नेवी

परिवहन को सुगम और सस्ता बनाने के लिए जलमार्ग बेहतर विकल्प है। इसका विकास होने और भविष्य में इन्हें एक-दूसरे से जोड़ने पर बाढ़ की समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। - रविशंकर सिंह, इंजीनियर मर्चेंट नेवी

रेल-सड़क मार्ग के समानांतर शुरू होगी जलपरिवहन सेवा, हल्दिया-इलाहाबाद के बीच इंटीग्रेटेड रीवर वॉटर फ्रंट कारीडोर की तैयारी

जुड़ेंगी सभी नदियां, बनेगा नेशनल वाटर ग्रिड

अच्छे दिनों की तैयारी

वाराणसी | वरिष्ठ संवाददाता

जल परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के लिए नदियों को जोड़कर एक 'नेशनल वॉटर ग्रिड' बनेगा। रेल व सड़क मार्ग के समानांतर जल परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने पांच जल परिवहन मार्गों की रूपरेखा बनायी है जिनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराख में जल परिवहन योजना पर काम शुरू हो गया है। वहीं, इंटीग्रेटेड रीवर वॉटर फ्रेट कारीडोर बनाने पर खास जोर है। इससे माल ढुलाई के क्षेत्र में नयी पहल होगी। विश्व बैंक के आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग से पूरी होने वाली इस परियोजना पर 42 सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे।

यह जानकारी शुक्रवार को होटल क्लार्क्स में आयोजित पत्रकारवार्ता में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन अमिताभ वर्मा ने दीं। उन्होंने कहा कि केवल सड़क व रेल मार्ग पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। जलपरिवहन सेवा के लाभ को देखते हुए सभी राज्यों में वाटर वेज निदेशालय का भी गठन जरूरी है। इसलिए सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने यहां एक निदेशालय बनाएं जिससे कि जलपरिवहन सेवा को गति मिल सके और राज्यों का भी आर्थिक विकास हो।

अगले तीन साल में कार्गो सेवा शुरू : श्री वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने हल्दिया से इलाहाबाद तक जलपरिवहन सेवा शुरू करने के लिए 42 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1620 किमी लंबे मार्ग पर अगले पांच साल के अंदर जलपरिवहन शुरू करने की योजना है लेकिन निवेशकों, उद्यमियों, शिपिंग एवं अन्य सेक्टर से जुड़े लोगों के उत्साह को देखते हुए यह सेवा अगले तीन साल में शुरू कर दी जाएगी।

गंगा क्षेत्र में 21 पॉवर प्लांट : गंगा के तटीय इलाके में 21 पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनमें 10 परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। बाकी पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं को शुरू करने पर 90 हजार मीट्रिक टन कोयला हर माह पॉवर प्लांट को चाहिए, जो रेल व सड़क मार्ग से संभव नहीं है। इसका विकल्प जलमार्ग ही है। इसके अलावा देश में अन्य सेक्टरों को संचालित करने के लिए 35 मिलियन टन कोयला आयात करने का निर्णय लिया गया है।

चालीस एकड़ जमीन की जरूरत : वाराणसी के राल्हूपुर में टर्मिनल बनेगा। इनमें 15 एकड़ जमीन पहले अधिग्रहीत की जा चुकी है। बीस एकड़ जमीन की और जरूरत है। इसके लिए किसानों से बातचीत हो चुकी है। श्री वर्मा ने कहा कि जमीन मिलते ही टर्मिनल बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

होटल क्लार्क्स में आयोजित 'इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट' के वर्कशाप में बोलते अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन अमिताभ वर्मा।

नेशनल इंडस्ट्रियल कारीडोर बनेगा

उन्होंने बताया कि गंगा जल परिवहन सेवा शुरू हो जाने पर 70 हजार करोड़ का निजी निवेश होगा। 60 हजार को प्रत्यक्ष एवं 40 हजार लोगों को परोक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अमृतसर, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता के बीच 'नेशनल इंडस्ट्रियल कारीडोर' बनाने की योजना तैयार की है। यह योजना अगले चार सालों में मूर्त रूप ले लेगी। नदी किनारे नए उद्योग स्थापित होंगे। इस कारीडोर के बनने के बाद गंगा जल मार्ग से माल की ढुलाई बहुत की सुव्यस्थित एवं सस्ता हो जाएगा।

वाराणसी-गाजीपुर के बीच गंगा में ड्रेजिंग दिसम्बर से

वाराणसी से गाजीपुर तक दिसम्बर से ड्रेजिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। योजना पर कुल 19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया गया है। पानी का स्तर समान बनाए रखने के लिए इलाहाबाद से पटना के बीच चार बैराज बनाए जाएंगे। इनमें इलाहाबाद-वाराणसी के बीच दो बैराज होंगे। गाजीपुर व पटना के बीच एक-एक बैराज बनाए जाएंगे। श्री वर्मा के अनुसार वाराणसी-इलाहाबाद के बीच गंगा में काफी गहराई है लेकिन वाराणसी- गाजीपुर के बीच सामान्य दिनों में 1.2 मीटर पानी रहता है। इसलिए गाजीपुर-वाराणसी के बीच ड्रेजिंग पहले करायी जाएगी।

16 स्थानों पर बनेंगे फ्लोटिंग टर्मिनल

हल्दिया से इलाहाबाद के बीच 16 स्थानों पर फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए जाएंगे। इनमें हर जिले में एक टर्मिनल होगा जिससे कि जहाजों से आने वाले मॉल को आसानी से उतारा जा सके। अब तक कोलकाता एवं पटना में दो टर्मिनल गंगा में बने हैं। आने वाले दिनों में बनारस में एक टर्मिनल बनेगा।

जलपरिवहन में आड़े नहीं आएगी कछुआ सैंक्चुरीः अफसरों का कहना है कि जलपरिवहन सेवा में कछुआ सैंक्चुवरी बाधा नहीं बनेगा। इसके लिए वन एवं पर्यावरण, जल परिवहन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय की संयुक्त टीम काम कर रही है। शीघ्र ही दिक्कतें दूर हो जाएंगी।

'इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट' पर आयोजित कार्यशाला में मौजूद विशिष्टजन। • हिन्दुस्तान

नदियों का नेशनल ग्रिड बने

वाराणसी (एसएनबी)। भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग के चेयरमैन अमिताभ वर्मा ने कहा कि जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए देश में फैली नदियों का नेशनल ग्रिड बनाया जाना चाहिए। ताकि रेल व सड़क मार्ग के समानांतर जल परिवहन सेवा शुरू की जा सके। भारत सरकार ने पूरे देश में पांच जल मार्ग घोषित कर रखा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र व बराक (असम) में जल परिवहन शुरू करने की योजना प्रगति पर है। भविष्य में परिवहन के लिए सिर्फ सड़क व रेलमार्ग पर निर्भर नहीं रह जा सकता है। श्री वर्मा ने कहा कि सभी राज्यों में अलग जल मार्ग निदेशालय का गठन किया जाना जरूरी है।

- सभी राज्यों में अलग से जल मार्ग निदेशालय का गठन हो
- वाराणसी से गाजीपुर तक ड्रेजिंग कार्य इसी माह शुरू होगा
- इलाहाबाद से वाराणसी के बीच दो बैराज बनेंगे
- रामनगर में 40 एकड़ में बनेगा टर्मिनल

श्री वर्मा ने शुक्रवार को शहर के एक होटल में नेशनल इनलैण्ड नेविगेशन इस्टीट्यूट तथा आशा इण्टरनेशन इंस्टीट्यूट आफ मेरिन टेक्नोलाजी की ओर से आयोजित 'अन्तर्देशीय जल परिवहन-व्यापार की सम्भावना' विषयक अन्तरराष्ट्रीय गोष्ठी में भाग लेने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने पिछले दिनों हल्दिया से इलाहाबाद तक जल परिवहन सेवा शुरू करने के लिए 42 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 1620 किमी लम्बे इस मार्ग पर अगले पांच वर्ष के अन्दर जल परिवहन शुरू करने की योजना थी। लेकिन इसमें निवेशकों, उद्यमियों के उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि यह परिवहन सेवा अगले तीन वर्षों में शुरू कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि गंगा बेल्ट में 11 पावर प्लान्ट लगाये जा रहे हैं। 10 परियोजनाओं को स्वीकृति मिलनी बाकी है। इन परियोजनाओं के शुरू होने पर 90 हजार मीट्रिक टन कोयला हर माह चाहिए जिसकी आपूर्ति रेल व सड़क मार्ग से सम्भव नहीं है। इसके लिए विकल्प सिर्फ गंगा जल मार्ग ही रहेगा। इसके अलावा केन्द्र ने 35 मिलियन टन कोयला विदेश से निर्यात करने का निर्णय किया है। जिसमें से 15 मिलियन टन

(शेष पेज 17)

नदियों का...

कोयला गंगा बेल्ट के उद्योगों को दिया जाना है, उसके लिए हम सेवा देने को तैयार है। कुल मिलाकर प्राधिकरण के सामने लक्ष्य और चुनौतियां हैं। पटना के बाद वाराणसी प्राधिकरण का 'टारगेटेड प्वाइंट' बनेगा। उन्होंने बताया कि गंगा जल परिवहन सेवा शुरू होने पर 70 हजार करोड़ के निजी निवेश की सम्भावना है। 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 40 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। केन्द्र सरकार ने अमृतसर, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी तथा कोलकात्ता को नेशनल इण्डस्ट्रियल कोरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। जो अगले तीन-चार साल में मूर्त रूप ले लेगा। इसके बनने के बाद गंगा जलमार्ग से माल की ढुलाई बहुत सुगम, सुव्यस्थित व सस्ती हो जायेगी। गंगा जल परिवहन सेवा शुरू करने के लिए वाराणसी से गाजीपुर तक सितम्बर के अन्त से ड्रेजिंग कार्य शुरू कर दिया जायेगा। इस पर 19 करोड़ खर्च आयेगा। ग्लोबल टेण्डर भी जारी कर दिये गये हैं। इलाहाबाद से पटना के बीच चार स्थानों पर बैराज बनाया जाना प्रस्तावित है। इलाहाबाद से वाराणसी के बीच दो, वाराणसी से गाजीपुर के बीच एक तथा गाजीपुर से पटना के बीच एक बैराज बनना है। जलमार्ग पर कोलकाता व पटना में टर्मिनल है और वाराणसी में टर्मिनल बनाया जायेगा। टर्मिनल के लिए रामनगर के पास 40 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। 15 एकड़ जमीन प्राधिकरण के पास पहले से है। 16 स्थानों पर फ्लोटिंग टर्मिनल बनाया जायेगा। वाटर स्पोर्ट्स व टूरिज्म प्रमोशन की योजनाओं पर भी विचार हो रहा है।

बनारस में बनेगा स्थायी टर्मिनल

वाराणसी (ब्यूरो)। देश के सबसे लंबे इलाहाबाद-हल्दिया जलमार्ग पर छह स्थायी और 16 फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए जाएंगे। कोलकाता, फरक्का, पटना, वाराणसी और इलाहाबाद में स्थायी टर्मिनल के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गंगा की गहराई बढ़ाने के लिए ड्रेजिंग (बालू का खनन) दिसंबर से शुरू कराया जाएगा। भविष्य में देश के सभी पांच जलमार्गों को आपस में जोड़कर नेशनल ग्रिड बनाने की भी योजना है। इनके जरिये 70 हजार करोड़ के वार्षिक व्यापार का लक्ष्य रखा गया है।

गंगा में जल परिवहन का प्रोजेक्ट का खाका तैयार कर रही जहाजरानी मंत्रालय की संस्था नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने शुक्रवार को शेष पेज 8 पर

गंगा में जल परिवहन

- दिसंबर से वाराणसी-गाजीपुर में होगी ड्रेजिंग
- टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू
- पांच जलमार्गों को मिलाकर बनेगा नेशनल ग्रिड
- कार्यशाला में प्रोजेक्टर से दिखाया गया प्रोजेक्ट का खाका

पांच प्रमुख जलमार्ग

- इलाहाबाद-हल्दिया मार्ग, गंगा (1620 किमी., चार राज्यों को होगा फायदा)
- सादिया से दुबरी, ब्रह्मपुत्र (891 किमी.)
- कोल्लम से कोट्टापुरम, वेस्ट कोस्ट कैनाल (205 किमी. केरल में)
- कर्किडा से पांडिचेरी जलमार्ग, कृष्णा-गोदावरी (1095 किमी.)
- उड़ीसा से वेस्टबंगाल, ब्राह्मणी नदी, ईस्ट कोस्ट कैनाल, मताई नदी और महानदी (623 किमी.)

प्रस्तावित जलमार्ग

- लखीपुर से भंगा मार्ग, बराक नदी असम (121 किमी.)

(इसे अभी सरकार की हरी झंडी मिलनी बाकी है)

रामनगर में ठहरेंगे जलपोत : पेज 3 पर

IWAI proposes directorates at state level

Times News Network

Varanasi: The Inland Waterways Authority of India (IWAI) has proposed for the establishment of IWAI directorates at state level for the development of inland water transport sector.

"Since water is a state subject, it is essential to establish IWAI directorates at the state level for promotion of inland water transport," said Amitabh Verma, chairman of IWAI. Verma was here on Friday to attend a function. He said that the state governments would be urged to establish directorates in their respective states. **P 4**